



जेन-जी की नब्ज को संघ ने समझा मोहन भागवत का मुंबई में नई युवा पीढ़ी के साथ संवाद

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वैचारिक रिश्तों के बीच, संघ प्रमुख मोहन भागवत का हर एक बयान सियासी गलियायों में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जाता है। संघ प्रमुख जब कभी कोई बात कहते हैं तो कभी-कभी बीजेपी की नीतियों के समर्थन के तौर पर देखा जाता है तो कभी लगता है कि किसी बदलाव या सुधार का संकेत है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत का मुंबई में गुरुवार को जेन-और जेन-अल्फा यानी नई युवा पीढ़ी के साथ उनकी बातची सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि आने वाले समय में राजनीतिका और सामाजिक दिशा तय करने वाला एक गहरा वैचारिक संदेश है। जेन-जी की साथ संवाद के दौरान मोहन भागवत के जवाब, भाषा का चुनाव और बाँड़ी लँग्वेज अहम संकेत थे।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन खत्म होने के दो हफ्ते बाद युवा पीढ़ी के साथ उनकी बातचीत क बड़ा संकेत है। बीजेपी छात्रों-युवाओं के नब्ज को समझने में नाकाम रही है, आरएसएस ने उसे बाखूबी समझते हुए युवा पीढ़ी को साधने की कोशिश शुरू कर दी है।

संघ प्रमुख का यह आउटरीच इवेंट उन छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बाद हुआ है, जिन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से बढ़ती दूरी को उजागर किया, जो अब सत्ता से सवाल पूछने, जवाब मांगने और अपनी शिकायतों को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में संघ प्रमुख ने

युवाओं के साथ संवाद किया। भागवत शायद ही कभी अंग्रेजी में बोलते हों, लेकिन गुरुवार को जेन के साथ संवाद में उसी अंदाज, अंग्रेजी और हिंदी दोनों



भाषाओं में बातचीत कर रहे थे।

युवा पीढ़ी की शिकायतों को संघ प्रमुख ने सुना और बकायदा माना भी। उन्होंने छात्रों के विरोध करने के अधिकार का बचाव किया। साथ ही इस बात को भी खारिज कर दिया कि विरोध करने वाले युवा %गठ-विरोधी% करार दिया जाए। भागवत ने बेरोजगारी, शिक्षा और आरक्षण के मुद्दे पर बात की। सबसे अहम

बात यह रही कि उन्होंने युवा पीढ़ी के बारे में एक बुनियादी बात समझा कि यह सवाल पुछती है और बदले में तार्किक जवाब की उम्मीद करती है।

मोहन भागवत विरोध करने वालों के हर तरीके का समर्थन नहीं कर रहे थे। उन्होंने खास तौर पर डॉ।भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि आंदोलन करने के कुछ तरीके होते हैं, लेकिन यह बात भी तब कही, जब उन्होंने यह मान लिया था कि युवा इसलिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी

तिरोध का अधिकार और लोकतंत्र का सबक

संघ प्रमुख भागवत ने यह नहीं कहा कि जेन और युवा पीढ़ी को विरोध करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विरोध भी लोकतांत्रिक बातचीत का एक तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा कि विरोध भी बातचीत का एक ज़रिया है और तर्क दिया कि जब

संवाद और बातचीत नहीं होती, तो विरोध मुद्दों को चर्चा में लाने का एक तरीका बन जाता है। संघ प्रमुख के द्वारा किया गया यह फर्क मायने रखता है।

मोहन भागवत विरोध करने वालों के हर तरीके का समर्थन नहीं कर रहे थे। उन्होंने खास तौर पर डॉ।भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि आंदोलन करने के कुछ तरीके होते हैं, लेकिन यह बात भी तब कही, जब उन्होंने यह मान लिया था कि युवा इसलिए विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में असल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

भागवत ने कहा कि आंदोलन को इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए और उसका समाधान किया जाना चाहिए। संघ के लिए राजनीतिक रूप से यह काम का फर्क है, यह किसी शिकायत की जायज बात को विरोध के दौरान की गई हर कार्रवाई की जायज बात से अलग करता है। सीजेपी आंदोलन के दौरान बीजेपी की प्रतिक्रिया ने अक्सर इसी फर्क को धुंधला कर दिया। नतीजा यह हुआ कि परीक्षा में गड़बड़ियों और हथशस्त्र-त पेपर लोक को लेकर शुरू हुआ विरोध धीरे-धीरे एक बड़ी बहस में बदल गया कि क्या युवा भारतीयों को सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाने का अधिकार है भी या नहीं। जब तक केंद्र सरकार बातचीत के लिए आगे बढ़ी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अहम राजनीतिक मांग को माना, तब तक विरोध का महत्व उसकी शुरुआती वजह से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था।

पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में राहुल को हाईकोर्ट से झटका

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2018 में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2019 में मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ जारी



क्रिए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एन आर बोकरर की एकल पीठ ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गिरागंव मजिस्ट्रेट की ओर से 28 अगस्त 2019 को जारी आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश के तहत उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत पर कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि उसे मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए आदेश में ऐसी कोई ‘कानूनी गलती या विकृति’ नहीं मिली, जिसके आधार पर अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायमूर्ति बोकरर ने कहा कि आदेश में कोई खामी नहीं है और इसलिए राहुल गांधी की याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने नवंबर 2021 के उस आदेश को जारी रखा।

मणिपुरी संगीतकार की हत्या पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चोंगथम विक्रम सिंह मणिपुर के एक प्रसिद्ध संगीतकार, अपने घर के बाहर कुछ लोगों



से शोर कम करने के लिए कहने नीचे गए थे। उन्हें इसके लिए पीट-पीटकर मार डाला गया। एक पिता को अपने ही घर के बाहर, अपने ही देश की राजधानी में हत्या कर दी गई। ऐसी कई घटनाओं के बाद आज दिल्ली में रहने वाला हर पूर्वोत्तर परिवार एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? राहुल गांधी ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए शाह का गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस क्या कर रहे हैं? मामले की तेजी से जांच होनी चाहिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। विक्रम जी के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। राहुल गांधी ने यह बात मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कही।

दिल्ली विस अध्यक्ष को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को मंगलवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने बताया कि वे सभी ज़रूरी जाँच-पड़ताल के लिए प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। अभी और जानकारी का इंतज़ार है। इससे पहले, इस साल अप्रैल में दिल्ली



विधानसभा को लगातार कई बम की धमकियाँ मिलने के बाद गुप्ता को जेड-कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, यह फ़ैसला कई बार मिली खास धमकियों और हाल ही में सुरक्षा में हुई एक बड़ी चूक के बाद लिया गया। बढ़ाई गई जेड-कैटेगरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत, गुप्ता को एक खास सुरक्षा टीम से चौबीसों घंटे सुरक्षा और साथ में एक समर्पित एस्कॉर्ट गाड़ी मिली। सचिवालय और स्पीकर के ऑफिस को लगभग छह से सात धमकी भरे ईमेल मिले थे। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को डाक से आए एक पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। पत्र में चेतावनी दी गई थी कि उन्हें जल्द ही कट्टर आतंकवादी मार डालेंगे।

तमिलनाडु विधानसभा में मीसा पर महाभारत

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा में मीसा, सरकारिया आयोग और पिछली डीएमके सरकारों से जुड़े कथित मामलों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया। डीएमके ने मुख्यमंत्री विजय के बयानों को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग की, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसके बाद स्पीकर ने मार्शल को डीमके विधायकों को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया। डीएमके विधायक ई.वी. वेलु ने मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि जांच के दायरे में चल रहे विजिलेंस मामलों का सदन में जिक्र करना विधानसभा की परंपरा का उल्लंघन है। हंगामे के बीच स्पीकर ने वेलु को अपनी बात रखने की अनुमति दी। वेलु ने कहा कि मामलों को पढ़ना परंपरा का उल्लंघन है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने मीसा और सरकारिया आयोग के बारे में बात की थी। मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान विजिलेंस मामलों को पढ़ना परंपरा का उल्लंघन है।

बीआरएस विधायक की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने किया स्वागत

हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस नेता मोथा रोहित ने मंगलवार को बीआरएस विधायक टी. मधुमदन राव (उर्फ टाटा मधु) और एन. नवीन कुमार रेड्डी की गिरफ्तारी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना विधानसभा स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर की गई यह कार्रवाई सही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मधु को गिरफ्तार करके सही कदम उठाया है;



मधु पर एक दलित स्पीकर का अपमान करने का आरोप है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस टाटा मधु के इस्तीफे की मांग को लेकर गांधी भवन में विरोध प्रदर्शन करेगी। मीडिया से बात करते हुए रोहित ने कहा, मैं केसीआर और केटीआर से सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इसे गैर-कानूनी गिरफ्तारी कैसे कह सकते हैं? आपको इस गिरफ्तारी का स्वागत करना चाहिए। बीआरएस का दलितों का अपमान करने का लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार ने मधु को गिरफ्तार करके सही काम किया है, जिन्होंने एक दलित स्पीकर का अपमान किया है। हम आज गांधी भवन में टाटा मधु के इस्तीफे की मांग को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, ब्रम्ह नेता दासोजू श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान ब्रम्ह नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बल प्रयोग करने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने बिगाड़ दिया पाकिस्तान का खेल

नीरज कुमार दुबे

तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। मक्का पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाली तीनों देशों ने इसको लेकर ऐसी ऐसी बातें कहीं जिससे रक्षा रणनीति के क्षेत्र में इस समझौते की खबर आग की तरह फैल गयी। लेकिन जैसे जैसे समझौते के बिंदु सामने आने लगे वैसे वैसे दुनिया को समझ आ गया कि यहां आग से ज्यादा धुआं है। हम आपको बता दें कि बड़े-बड़े दावों और सामूहिक सुरक्षा के संदेश के बावजूद इस समझौते की सैन्य क्षमता और वास्तविक प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच इस पैक्ट के पैकेट की हवा पूरी तरह

निकालने के लिए मोदी सरकार की कूटनीति भी तेज हो गई है। भारत साफ तौर पर यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि पाकिस्तान इस समझौते का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कोई रणनीतिक दबाव बनाने के लिए नहीं कर सके।

देखा जाये तो शुरुआत में ऐसा लगा था कि मक्का पैक्ट एक ऐसा भू-राजनीतिक प्रयोग बनकर उभर रहा है, जिसके तार पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया और संभवतः बंगाल की खाड़ी तक फैल सकते हैं। समझौते का मूल संदेश यह था कि तीनों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस घोषणा के पीछे जितनी बड़ी सामरिक महत्वाकांक्षा

है, उतनी ही गहरी अस्पष्टता भी है। इसी अस्पष्टता में पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद छिपी है और भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल भी है। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में एक नया इस्लामिक नाटो बनने जा रहा है, या फिर यह राजनीतिक संदेश, सामरिक दबाव और प्रतिरोधक क्षमता का एक बड़ा लेकिन सीमित प्रयोग भर है?

देखा जाये तो मक्का समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी भौगोलिक और सामरिक असंगति है। पाकिस्तान न तो पश्चिम एशिया का हिस्सा है और न ही खाड़ी क्षेत्र का। तुर्किये की सुरक्षा चिंताएं सीरिया, इराक, कुर्द उग्रवाद, शरणार्थियों और अपनी दक्षिणी सीमाओं



से जुड़ी हैं। सऊदी अरब के सामने ईरान, यमन के हूती और क्षेत्रीय अस्थिरता की चुनौतियां हैं। पाकिस्तान की प्राथमिक चुनौती बिल्कुल अलग है। ऐसे में सवाल उठता है कि तीनों देशों को साझा दुश्मन की परिभाषा आखिर क्या है?यही कारण है कि इस समझौते को एक मजबूत सैन्य गठबंधन की बजाय फिलहाल स्ट्रेटेंजिक सिग्नलिंग और डिटेरेंस का प्रयोग कहना अधिक

उचित होगा। यहां इतिहास भी कई सवाल खड़े करता है। 2015 में हूती हमलों के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब की रक्षा के लिए सीधे सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाई थी। 2019 में अबकैक और खुरैस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले के समय भी कोई स्वचालित पाकिस्तानी सैन्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूसरी तरफ, जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा तनाव हुआ, तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता नहीं दी। ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि जब पुराने द्विपक्षीय समझौते संकट के समय सीधे सैन्य कार्रवाई में नहीं बदले, तो नया त्रिपक्षीय समझौता वास्तव में कितना असरदार साबित होगा?लेकिन भारत के लिए

खतरे का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि तुर्किये या सऊदी अरब वास्तव में पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़ेंगे या नहीं? सामरिक गारंटी युद्ध शुरू होने से पहले ही राजनीतिक व्यवहार बदल देती है। पाकिस्तान को यह संदेश मिल सकता है कि उसके पीछे अब एक व्यापक सुरक्षा ढांचा खड़ा है। खासकर तब, जब तुर्किये लगातार पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य समर्थन करता रहा है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी। उसका रुख भारत के खिलाफ स्पष्ट था।

यही नहीं, 31 अगस्त को इस्लामुल में हुई बैठक में इस समझौते को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। इसमें एक स्थायी सचिवालय बनाने, सैन्य

सहयोग बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी करने और मिलकर रक्षा उपकरण तैयार करने की बात हुई। रियाद में सचिवालय बनाने और शुरुआती वर्षों में पाकिस्तानी महामसंचिब नियुक्त करने की योजना से साफ है कि इस समझौते को एक स्थायी और संगठित ढांचा देने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इमर खान की सऊदी अरब, तुर्किये और मिस्र के विदेश मंत्रियों से हालिया बातचीत भी बताती है कि इस दिशा में कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब सबसे संवेदनशील मोर्चा है बांग्लादेश। यदि ढांचा इस समझौते में शामिल होता है, तो मामला भारत के लिए पश्चिमी सीमा तक सीमित नहीं रहेगा।



प्रधानमंत्री आवास योजना विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव

पक्के घरों से बदल रही गांवों की तस्वीर,
आत्मसम्मान से भर रहा हर परिवार



“हमारी सरकार का लक्ष्य है, कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे। पक्का घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव है।
श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, यह केवल एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का अभियान है। विकसित भारत के निर्माण में आवास, सम्मान और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण भूमिका है।
श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पक्का घर : सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि का आधार

छत्तीसगढ़ में आवास योजना का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ आज प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन राष्ट्रीय उदाहरण बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य ने आवास निर्माण को केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनकल्याण के व्यापक अभियान का स्वरूप दिया है। गांव-गांव तक पहुंची इस पहल ने लाखों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थावित्य का नया अध्याय जोड़ा है।

एक समय था जब प्रदेश के अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में परिवार कच्चे मकानों, झोपड़ियों और अस्थायी आवासों में जीवनयापन करने को मजबूर थे। बरसात में टपकती छतें, गर्मियों में असहनीय तापमान और प्राकृतिक आपदाओं के बीच जीवन संघर्ष का पर्याय बन चुका था। आज वही परिवार मजबूत पक्के मकानों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'सबके लिए आवास' के संकल्प को छत्तीसगढ़ सरकार ने मिशन मोड में धरातल पर उतारते हुए प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया है।

आवास से आगे बढ़कर सामाजिक परिवर्तन

प्रधानमंत्री आवास योजना ने केवल ईट और सीमेंट के ढांचे खड़े नहीं किए हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नई इबारत लिखी है। प्रदेश के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों, आदिवासी बहुल इलाकों और नक्सल प्रभावित अंचलों तक विकास की मुख्यधारा पहुंचाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आज हजारों गांवों में नए आवासों के साथ बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, गैस कनेक्शन, सड़क और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है। इससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला है।

आवास अब केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक सम्मान का आधार बन गया है।



नया घर, नई उम्मीद

सुशासन, तकनीक और पारदर्शिता का मॉडल

छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक और सुशासन को प्राथमिकता दी है।

तकनीक से पारदर्शिता

- डिजिटल मॉनिटरिंग**
हर आवास की प्रगति पर निरंतर नजर
- जियो टैगिंग**
प्रत्येक आवास का भौगोलिक सत्यापन
- सीधा लाभ**
हस्तांतरण लाभ सीधे हितग्राही के खाते में
- जन सहभागिता**
आवास मित्र, पंचायत और स्थानीय हितग्राहियों की सक्रिय भूमिका
- पारदर्शिता और जवाबदेही**
शिकायत निवारण और ऑनलाइन निगरानी

डिजिटल मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, ऑनलाइन सत्यापन, हेलपलाइन सेवाएं और तकनीकी निगरानी तंत्र के माध्यम से प्रत्येक आवास की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इससे योजना में पारदर्शिता बढ़ी है और लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है।

आदिवासी अंचलों में विकास का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ने विकास की नई कहानी लिखी है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवार अब पक्के और सुरक्षित घरों में जीवन यापन कर रहे हैं।

पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से विशेष पिछड़ी जनजातियों तक विकास की किरण पहुंची है।

इन क्षेत्रों में आवास निर्माण के साथ-साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों का भी विस्तार हुआ है।



रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिली नई दिशा

26 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति



विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए 33000 आवासों की स्वीकृति



आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों के लिए विशेष 15000 आवास



महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी

निर्माण सामग्री आपूर्ति और भवन निर्माण सहयोग से विकास की मुख्यधारा से जुड़ते परिवार और बढ़ती आत्मनिर्भरता।

जब घर बना, तब बदली जिंदगी

बस्तर, सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, सक्ती, मुंगेली और प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके लिए पक्का मकान कभी एक सपना था आज वही सपना साकार हो चुका है। पक्का घर मिलने के बाद बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हुई हैं और परिवार में आत्मविश्वास बढ़ा है।



महिलाओं के नाम पर बढ़ रहा स्वामित्व और सम्मान

योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवास महिलाओं के नाम अथवा संयुक्त स्वामित्व में स्वीकृत किए गए हैं। इससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण मजबूत हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल रही, बल्कि परिवार की आर्थिक योजनाओं, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक निर्णयों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

जल संरक्षण के साथ हरित विकास

छत्तीसगढ़ सरकार ने आवास निर्माण को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा है। 'मोर गांव-मोर पानी' जैसे अभियानों के माध्यम से नए आवासों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल भविष्य के लिए जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में बढ़ा कदम है।



डिजिटल छत्तीसगढ़, मजबूत कदम

ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था, डिजिटल सत्यापन और तकनीकी निगरानी ने योजना की विश्वसनीयता बढ़ाई है। डिजिटल माध्यमों से शिकायत निवारण और प्रगति समीक्षा की व्यवस्था ने सुशासन की नई मिसाल प्रस्तुत की है।



रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिली नई दिशा

प्रधानमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्रदान की है। आवास निर्माण कार्यों से हजारों स्थानीय श्रमिकों, राजमिस्त्रों, निर्माण सामग्री विक्रेताओं और स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। कई जिलों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह निर्माण सामग्री आपूर्ति, भवन निर्माण सहयोग और अन्य सेवाओं से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

संवाद-48873/1



विकसित भारत - विकसित छत्तीसगढ़ की ओर

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से
समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की ओर



संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल से अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात

रायपुर। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय



महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल श्री रमेन डेका से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में राज्यपाल को विस्तृत जानकारी दी। साथ ही समाज की ओर से राज्यपाल रमेन डेका को इस गरिमामयी आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने महासभा की विभिन्न गतिविधियों और सामाजिक व पर्यावरणीय दायित्वों के संबंध में राज्यपाल को अवगत कराय। इस अवसर पर अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रभूषण वर्मा, सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

नवा रायपुर में खुलेगा बड़ा शैक्षणिक

केंद्र : वित्त मंत्री चौधरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी



खबर सामने आई है। प्रदेश में देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शामिल नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) का केजी से पीजी तक का कैंपस आने जा रहा है। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि नवा रायपुर में एनएमआईएमएस का कंप्लीट कैंपस विकसित होगा, जिसमें नर्सरी से लेकर स्कूलिंग, पीजी कॉलेज और मैनेजमेंट की पढ़ाई की सुविधा होगी। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एनएमआईएमएस को लाने के लिए काफी प्रयास किए गए। उनके मुताबिक, संस्था के पास कई राज्यो और शहरों के विकल्प मौजूद थे, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर लगातार प्रयास किए गए और इसमें प्रदेश सरकार ने अग्रणी भूमिका निभाई। ओपी चौधरी ने कहा कि एनएमआईएमएस का केजी से पीजी तक पूरा कैंपस छत्तीसगढ़ के लिए नई छलांग का प्रमाण है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी।

पेड मेंबरशिप मामला : वेलक का नामांकन अनहोल्ड, बंजारे को अभी इंतजार

रायपुर। छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार सत्येंद्र चेलक को राहत मिली है। पैसे देकर सदस्य बनाने के आरोप में होल्ड किया गया उनका नामांकन चुनाव कमेटी ने अनहोल्ड कर दिया है। जबकि बंजारे का नामांकन अभी भी होल्ड पर रखा गया है,उन्के समर्थकों को जवाब का इंतजार है। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हैं दोनों के बीच ही मुख्य मुकबला है एक भूपेश बबेल तो दूसरा देवेन्द्र यादव समर्थक हैं। पेड मेंबरशिप की शिकायत पर इनका नामांकन होल्ड किया गया था। वहीं एक तबके का कहना है कि अध्यक्ष ही क्या जितने भी पद पर चुनाव हो रहे हैं और जो मेंबर बनाये जा रहे हैं वे स्वयं तो पैसे देने से रहे। चाहे जैसे भी हो पैसे तो प्रत्याशी ही जमा कर रहे हैं। फिर तो सारे पद ही विवाद के घेरे में आ जायेंगे।

सीएम हेल्पलाइन 1076 ने संकट की घड़ी में निलंबर सिंह के परिवार तक पहुंचाई मदद

रायपुर। शासन की योजनाओं और जनसेवा से



संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 इसी दिशा में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रभावी माध्यम बन रही है। सरगुजा जिले के लुण्ड्रा तहसील के ग्राम बकनाकला, पोस्ट उदारी निवासी निलंबर सिंह के परिवार को भी कठिन समय में इसी व्यवस्था के माध्यम से राहत मिली। निलंबर सिंह की भतीजी की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। अचानक हुई इस घटना से परिवार गहरे सदमे में था। प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु के बाद शासन के प्रावधानों के तहत मिलने वाली राहत राशि के संबंध में परिवार को आवश्यक सहायता की जरूरत थी। अपनी समस्या के निराकरण के लिए निलंबर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत को संबंधित राजस्व अधिकारियों तक पहुंचाया गया, जिससे प्रकरण पर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। शिकायत प्राप्त होने के बाद तहसील स्तर पर प्रकरण की जांच की गई। आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत राशि स्वीकृत की गई। स्वीकृत राहत राशि परिवार के लिए आर्थिक सहारा बनी।

छात्राओं के पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचने पर सीएम साय सरख्त

फोन पर कलेक्टर से की बातचीत, जिम्मेदारी तय कर लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा जिले के शिवपुर एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं के अपनी समस्याओं को लेकर पैदल कलेक्ट्रेट के लिए निकलने की घटना को गंभीरता से लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विद्यालय में लंबे समय से समस्याएं बने रहने और छात्राओं को अपनी बात रखने के लिए इस तरह पैदल निकलने की स्थिति उत्पन्न होने पर कड़ी नाराजगी जताई।

मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टर से कहा कि बच्चियों को अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय से पैदल निकलना पड़े, यह स्थिति किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। यदि विद्यालय में लंबे समय से बिजली सहित अन्य समस्याएं बनी हुई थी



तो संबंधित अधिकारियों द्वारा समय रहते उनका समाधान क्यों नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को पूरे प्रकरण की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि

सामने लाई गई बिजली, शिक्षकों की कमी, नियमित पढ़ाई, मेस तथा साफ-सफाई से जुड़ी समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान पर्याप्त नहीं है, बल्कि

छत्तीसगढ़ी को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए सकारात्मक पहल

■ राज्यपाल रमेन डेका से छत्तीसगढ़ी भाषाविदों ने की भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से मंगलवार को लोक भवन में छत्तीसगढ़ी भाषाविदों ने भेंट कर छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने तथा इसके संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के संबंध में चर्चा की।

भाषाविदों ने राज्यपाल को छत्तीसगढ़ी भाषा की प्राचीनता, समृद्ध साहित्यिक परंपरा, व्याकरण, शब्दकोश एवं मानकीकरण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ी प्रदेश की राजभाषा एवं प्रमुख संपर्क भाषा है और लगभग डेढ़ करोड़ लोग इसका प्रयोग करते हैं।

राज्यपाल श्री डेका ने स्वयं पहल करते हुए इस विषय पर सार्थक चर्चा की। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और इसे आठवीं अनुसूची में



शामिल कराने की दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए कहा कि इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा के इतिहास, साहित्य, व्याकरण, शब्दकोश एवं अन्य संदर्भ सामग्री का व्यवस्थित संकलन किया जाएगा। इसके लिए विषय के विद्वानों एवं विशेषज्ञों से आवश्यक जानकारी और सुझाव भी लिए जाएंगे। राज्यपाल ने इस संदर्भ में असमिया और बोडो भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का उदाहरण भी दिया।

भाषाविदों ने बताया कि छत्तीसगढ़ी में 15

के लिए राज्य सरकार लगातार संसाधन उपलब्ध करा रही है। इन संसाधनों और योजनाओं का लाभ बच्चों तक सही ढंग से पहुंचे, यह सुनिश्चित करना मैदानी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। शासन की मंशा स्पष्ट है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ाई के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और सकारात्मक वातावरण मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बच्चे हम पर विश्वास करके आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी छोटी से छोटी समस्या को भी संवेदनशीलता के साथ सुनना और उसका समयबद्ध समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जिला प्रशासन को छात्राओं से संवाद बनाए रखने और विद्यालय की व्यवस्थाओं में किए जा रहे सुधारों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए।

9 सूत्रीय मांग को लेकर 22 से यातायात महासंघ का अनिश्चितकालीन महाबंद का ऐलान

रायपुर। अगर आप बस से ही आना जाना करते हैं तो 22 सितंबर से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने बस सेवा को बंद करने का ऐलान कर दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर 22 से प्रदेशभर में बसों के पहिए थम जाएंगे। प्रदेश में डीजल की बढ़ती कीमतों के बावजूद बस किराया नहीं बढ़ाए जाने से नाराज बस ऑपरेटरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि मांगें पूरी न होने पर 22 तारीख से राज्यभर में यात्री बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। बस मालिकों ने 9 सूत्रीय मांगें रखी है। इनमें बस किराया बढ़ाने के अलावा सिंगल स्लीपर सीट पर सिंगल टैक्स, ई-बसों को शहर की सीमा तक सीमित रखने, ऑल इंडिया परमिट



वाली बसों पर नकेल कसने और वीएलटीडी डिवाइस की नवीनीकरण दर घटाने जैसी मांगे है।

क्या है बस संचालकों की 9 मांगें?

- यात्री किराया बढ़ाया जाए।
- बसों में सिंगल स्लीपर का सिंगल टैक्स लिया जाए।
- ई-बस को शहर सीमा के भीतर

चलाया जाए।

- ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों को ग्रामीण क्षेत्र व बस स्टैंडों को संचालन प्रतिबंधित किया जाए।
- स्ट्रेज कैरिज बसों के समयचक्र में दूर बसों के मध्य अंतराल का निर्धारण किया जाए।

- वीएलटीडी डिवाइस के रिन्यूअल की दर में कमी कराई जाए।
- मैनुअल फिटनेस प्रदान किया जाए।
- प्रतिहस्ताक्षर को नियंत्रित किया जाए।
- सभी बसों में ऑनलाइन परमिट बनाने की सुविधा दी जाए।

मेट्स यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम

करियर के साथ जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए शिक्षा जरूरी : पुरंदर मिश्रा

रायपुर। मेट्स यूनिवर्सिटी ने नए दाखिला लेने वाले छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत करने और उन्हें यूनिवर्सिटी के एकेडमिक माहौल, सुविधाओं, अवसरों और कैम्पस लाइफ से परिचित कराने के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया। इस प्रोग्राम में विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए मिश्रा ने उन्हें उनकी एकेडमिक यात्रा के एक नए चरण में प्रवेश करने पर बधाई दी और उन्हें लगन, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रोत्साहित किया।

विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा न केवल एक सफल करियर बनाने में, बल्कि जिम्मेदार और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइस चांसलर डॉ. केपी यादव ने नए छात्रों का स्वागत किया और यूनिवर्सिटी के एकेडमिक विजन और शैक्षिक माहौल के बारे में बात की। उन्होंने छात्रों का मार्गदर्शन करने में फैकल्टी सदस्यों की भूमिका पर



प्रकाश डाला और नए छात्रों से क्लास रूम लर्निंग, प्रैक्टिकल गतिविधियों, रिसर्च-ओरिएंटेड सोच और यूनिवर्सिटी की अन्य पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

चांसलर गजराज पगारिया ने भी सभा को संबोधित किया और नए दाखिला लेने वाले छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने छात्रों को विभिन्न को-कुरिकुलर और एक्स्ट्रा-कुरिकुलर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपने एकेडमिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

डायरेक्टर जनरल प्रियेश पगारिया ने अपने संबोधन में छात्रों को उत्साह, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा के साथ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उन छात्रों के लिए एक

विशेष सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिन्होंने 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। मेधावी छात्रों को उनके उत्कृष्ट एकेडमिक प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। प्रोग्राम का समापन रजिस्ट्रार गोकुलानंद पांडा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिन्होंने छात्रों को संबोधित किया और उन्हें प्रेरित किया।

प्रोग्राम का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ, जिसमें छात्रों और यूनिवर्सिटी के गणमान्य व्यक्तियों ने ग्रुप फोटो खिंचवाई, जो एक नई और आशाजनक एकेडमिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था। इस मौके पर डॉ. शाइस्ता अंसारी, प्रोफेसर और हेड, मेट्स स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज – साइकोलॉजी, डॉ. आशीष सराफ, प्रोफेसर और हेड, स्कूल ऑफ साइंस और डॉ. अभिषेक गुरु हेड, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मौजूद थे। कार्यक्रम में अन्य सभी विभागों के प्रमुख, फैकल्टी सदस्य, यूनिवर्सिटी के अधिकारी और छात्र भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को खास अंदाज में मनाएगी भाजपा

■ विजय शर्मा ने कहा- प्रदेशभर में 36 लाख दिलों जलाए जाएंगे

रायपुर। देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर भाजपा ने विशेष तैयारियों की है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के साथ के लिए प्रदेशभर में 36 लाख आशीर्वाद के दिलों जलाए जाएंगे। प्रत्येक बूथ में 100 दिलों जलाने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सभी संभागीय, जिलों और विकासखंड मुख्यालयों में सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बस्तर सेवा संकल्प अभियान भी विशेष तौर पर चलाया जाएगा। बस्तर के गांव-गांव में आशीर्वाद के दिलों जलाए जाएंगे और लोगों को भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि स्कूलों में 'सेवा चित्र' कार्यक्रम होगा, जिसमें बच्चे पेंटिंग के जरिए सेवा और विकास से जुड़े विषयों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। वहीं स्कूलों और पंचायतों में 'सेवा स्मरण' कार्यक्रम के जरिए 25 वर्षों में हुए विकास कार्यों और बदलावों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अभियान के तहत आननबाड़ी



प्रकार ये प्रतिमाएं धार्मिक आस्था के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित संदेश को भी जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगी।

केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों द्वारा विभिन्न कौशल विकास एवं उत्पादन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में लगभग 10 बंदियों ने अत्यंत लगन, मेहनत और रचनात्मकता के साथ भगवान श्री गणेश की इन आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण किया है। यह पहल बंदियों के कौशल विकास, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें समाजोपयोगी एवं पर्यावरण हितैषी गतिविधियों से जोड़ने का सार्थक प्रयास है। मिट्टी की प्रतिमाओं में बीजों का समावेश इस कार्य को और विशेष बनाता है।

जेल अधीक्षक रायपुर श्री योगेश सिंह क्षत्री ने कहा कि केंद्रीय जेल रायपुर द्वारा बंदियों के पुनर्वास एवं आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर विभिन्न कौशल विकास एवं उत्पादन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में बंदियों द्वारा तैयार की गई ये बीजयुक्त पर्यावरण-अनुकूल गणेश प्रतिमाएं इस संदेश को साकार करती हैं कि आस्था और प्रकृति संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं।

बिहान योजना ने दिया आजीविका का सहारा

रायपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ('बिहान') के तहत संचालित इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक प्रभावी जरिया बन रही है। दंतवाड़ा जिले के कुआकोंडा और दंतवाड़ा विकासखंडों में बीते डेढ़ वर्षों से लागू इस योजना के जरिए लगभग 2,200 परिवारों को आजीविका के नए साधनों से जोड़ा जा चुका है। दंतवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकासखंड के ग्राम मुड़ापारा की निवासी रामबती नाग ने इस योजना का लाभ उठाकर मुर्गी पालन की शुरुआत की।

जिला प्रशासन के सहयोग से उन्हें जून माह में 80 रुपए प्रति चूना की दर से 100 चूजे और दूध दाना उपलब्ध कराया गया था। शुरुआती दौर में बीमारी के कारण करीब 25 से 30 चूजों की मृत्यु हो जाने से रामबती को झटका झुक लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बचे हुए चूजों का बेहतर रखरखाव और देखभाल करके उन्होंने अब तक करीब 25,000 रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर ली है। रामबती अपने तैयार मुर्गों को 500 रुपए प्रति किलो की दर से बेचती हैं, जिनका औसतन वजन 1 से 3 किलोग्राम तक होता है।

मोदी की नेतृत्व शैली की विशेषता मजबूत राष्ट्रवाद

कल्याणी शंकर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों की एक जटिल श्रृंखला के बीच अपनी सार्वजनिक छवि सुधारने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। भारत जैसे विविध और घनी आबादी वाले देश में एक नेता के रूप में, जहां विभिन्न समुदायों की अपनी अनूठी ज़रूरतें और अपेक्षाएं हैं, मोदी मजबूत जनसमर्थन बनाए रखने के लिए नागरिकों के साथ जुड़ने के महत्व को पहचानते हैं। जिन लोगों को वह सेवा करते हैं, उनके विविध अनुभवों और दृष्टिकोणों को सुनने की उनकी प्रतिबद्धता विश्वास को बढ़ावा देने और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 2014 में पद संभालने के बाद से, मोदी ने कई चुनौतियों का सामना किया है, जिन्होंने उनके नेतृत्व के प्रति जनता की धारणा और विश्वास को आकार दिया है।
यद्यपि वर्षों से उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता काफी हद तक बरकरार रही लेकिन 2024 में उन्हें तब झटका लगा, जब वह चुनावों में बहुमत से पीछे रह गए। इस बार, उनका नेतृत्व जांच के दायरे में है, खासकर आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी और कोविड-19 महामारी के विनाशकारी प्रभाव जैसी महत्वपूर्ण बाधाओं के बीच। इन घटनाओं ने विपक्षी दलों, आर्थिक विशेषज्ञों और व्यापक जनता की ओर से आलोचना को जन्म दिया है, जिससे उन नागरिकों में असंतोष फैला है, जिन्होंने महामारी के लॉकडाउन के दौरान नौकरियां गंवाई और व्यवसाय बंद होते देखे।
बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरंधति रॉय ने कहा है, ‘‘पी.एम. मोदी की छवि, जिसे करोड़ों रुपए की लागत से 24 वर्षों में बनाया गया था, उसे सी.जे.पी. द्वारा 2 सप्ताह में नष्ट कर दिया गया...।’’ आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मोदी को भारत और अपनी दोनों की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। शिखर सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जो भारत के बढ़ते प्रभाव और आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करने के मोदी के इरादे को दर्शाता है। वर्तमान आर्थिक संकट ने कई लोगों को मोदी की नीतियों और नेतृत्व क्षमताओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया है। इसके जवाब में, वह आर्थिक सुधार को गति देने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए पहलों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन चुनौतियों का डटकर सामना करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करके, मोदी मतदाताओं को आश्चस्त करना चाहते हैं कि वह रास्ता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अपनी सार्वजनिक छवि का पुनर्निर्माण और रीब्रांडिंग करना मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से, क्योंकि आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन पर उनका ध्यान इन कठिन समय में उनके नेतृत्व में विश्वास बहाल करने में मदद कर सकता है।
मोदी की नेतृत्व शैली की विशेषता मजबूत राष्ट्रवाद और निर्णायकता है, जिसने उन्हें समर्थकों का एक वफादार आधार दिलाया है। हालांकि, अपनी अपील को व्यापक बनाने के लिए, उन्हें एक अधिक समावेशी छवि प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, जो एकता और विविधता पर जोर देती है। ऐसा करके, वह उन संशयवादी मतदाताओं का विश्वास फिर से हासिल कर सकते हैं, जो खुद को अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। जैसे-जैसे राज्य चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक योजना और रणनीति तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। मोदी द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा में सुधारों में अपनी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने की संभावना है।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे....)

इसलिये हम तो खम टोक कर कहने के लिये तैयार हैं कि विश्व वाङ्मय मात्र पर जो पुराणों की अमिट छाप क़ञ्जलेप सी अङ्कित होती है उसे अब कोई भी पुराण-निन्दक नादान अपनी लपलपी जवान की कृतित्त कमान से छूटे हुवे व्याख्यानरूप बाण द्वारा छिन्न भिन्न नहीं कर सकता! और तो और जो लोग पुराण साहित्य को मटियामेट करने के ग्रन्थ लिखने चले थे तथा जो पुराणों को कोसने में ही अपने पाण्डित्य की पराकाष्ठा समझते थे वे महाशय भी पुराणों के सर्वांगपूर्ण चमत्कार से मोहित होकर आखीर पुराण-साहित्य की प्रशंसा करने के लिये ही विश्वास हुवे हैं। हम तत्तद् ग्रंथों से कतिपय पते यहां सप्रमाण अङ्कित करते हैं

जिससे सर्वसाधारण को जादू तो वह जो शिर चढ़ कर बोले इस लोकोक्ति का उज्ज्वल उदाहरण प्राप्त हो सके, यथा-



प्रो० रामदेव जी गौड़ (गुरुकुल--कांगड़ी) के विचार

पुराण और इतिहास हिन्दू-संस्कृति के विश्व-कोश हैं। (ब्राह्मण-सर्वस्व के पुराणाङ्क पृष्ठ 256 से)

लाला लाजपतराय के उद्गार

ईश्वरवादी पौराणिकों ने बौद्धधर्म के शस्त्र ग्रहण किये, आस्तिकता का जो प्रकाश पौराणिक धर्म ने व्याकुल आर्यसत्तान को दिखलाया था उसने बौद्ध-धर्म का पुलीटील बल भी छीन लिया ।

(दयानन्द जीवन चरित्र पृष्ठ 56)

पं० नरदेव शास्त्री ज्वालापुर महाविद्यालय की सम्मति

पुराणों में इतना मसाला भरा हुआ है, कि अज्ञ से अज्ञ पुरुष भी उनमें वर्णित कथा कहानियों द्वारा धर्म के उच्च से उत्तच तत्व को वेदशास्त्र के स्वाध्याय के बिना ही समझ सकते हैं।

(ब्रा० स० के पुराणाङ्क पृष्ठ 216 से-) **क्रमशः...**

रक्षा समझौते की आड़ में पाकिस्तान का बढ़ता सैन्य जमावड़ा

कातिलाल मांडेठ

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लंबे समय से दबाव में है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सैन्य तैयारियों का विस्तार लगातार जारी है। सऊदी अरब और तुर्किये के साथ हाल में हुए रक्षा सहयोग ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। पाकिस्तान के लिए यह साझेदारी केवल कूटनीतिक समर्थन तक सीमित दिखाई नहीं देती, बल्कि आधुनिक ड्रोन, मिसाइल तकनीक और लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यही वजह है कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ इस नए सैन्य समीकरण को गंभीरता से देख रहे हैं।

अगस्त में पाकिस्तान के विभिन्न सैन्य हवाई अड्डों पर तुर्किये के सैन्य परिवहन विमानों की आवाजाही ने भी इन आशंकाओं को बढ़ाया है। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ ही दिनों के भीतर तुर्किये के सी-130 और ए-400एम जैसे परिवहन विमानों ने पाकिस्तान के अलग-अलग एयरबेस का इस्तेमाल किया। इस गतिविधि को दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि हथियारों की वास्तविक मात्रा और पूरी खेप के बारे में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध जानकारी सीमित है, लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक और उपकरणों का सहयोग कोई नई बात नहीं है।

तुर्किये पहले से ही पाकिस्तान के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका है। ड्रोन तकनीक से लेकर नौसैनिक परियोजनाओं और लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण तक दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। पाकिस्तान को तुर्किये की बायरकार टीबी2 और अर्किंस जैसी ड्रोन प्रणालियों में रुचि है। इन प्लेटफॉर्मों की खासियत यह है कि इनका इस्तेमाल निगरानी के साथ-साथ सटीक हमलों के लिए भी किया जा सकता है। अर्किंस जैसे भारी ड्रोन अपेक्षाकृत अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम हैं और लंबी अवधि तक अभियान में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।



इसके साथ ही तुर्किये की केमाकेश जैसी मानव रहित वरूज मिसाइल तकनीक भी पाकिस्तान की सैन्य क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसी प्रणालियां आधुनिक युद्ध में पारंपरिक हथियारों से अलग भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इन्हें लक्ष्य की पहचान और सटीक हमले के लिए आधुनिक सेंसर तथा मार्गदर्शन तकनीक से जोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान के लिए इस तरह की तकनीक हासिल करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में ड्रोन और मानवरहित प्रणालियां युद्ध की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुकी हैं।

तुर्किये का सहयोग केवल नए हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ाने और एनएफवीक्स तथा हथियार प्रणालियों को आधुनिक बनाने में भी तुर्किये की भूमिका रही है। पुराने लड़ाकू विमानों की सेवा अवधि और परिचालन क्षमता बनाए रखना किसी भी वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से पाकिस्तान अपने मौजूदा सैन्य संसाधनों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ता दिखाई देता है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुआ मका संयुक्त रक्षा समझौता है। इस समझौते को तीनों देशों के बीच रणनीतिक और सैन्य सहयोग को संस्थागत रूप देने की कोशिश के रूप में देखा जा

समाचार पचीसा

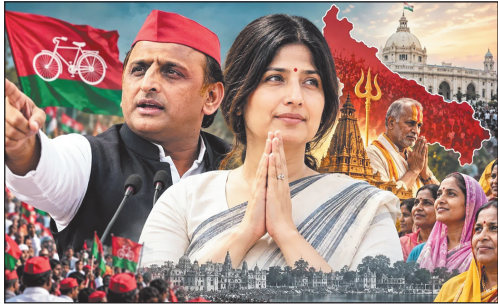
रायपुर, बुधवार 09 सितंबर 2026

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती से नहीं जीते जाते। यहां जाति, जन्मत, चेहरा और संदेश, इन चारों का सही तालमेल सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपनी पुरानी साइकिल में नए राजनीतिक पुर्जे लगाने में जुटे हैं। मकसद सपा को उसकी पुरानी छवि से बाहर निकालना है, जिसे विरोधी लंबे समय से एक खास सामाजिक दायरे और सत्ता में कथित तौर पर आक्रामक राजनीति से जोड़ते रहे हैं। अखिलेश की नई रणनीति में जातीय समीकरण भी है, हिंदू प्रतीक भी हैं, पीडीए का विस्वार भी है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिंपल यादव के रूप में एक नया और अपेक्षाकृत शांत चेहरा भी है।

देखा जाये तो अब तक डिंपल यादव की राजनीति अपेक्षाकृत संयमित और सीमित सार्वजनिक दायरे में दिखाई देती रही है। लेकिन हाल के समय में उनकी सक्रियता बढ़ी है। संसद से लेकर राजनीतिक मुद्दों तक उनकी मौजूदगी ज्यादा मुखर हुई है। यही बदलाव महज सामान्य राजनीतिक सक्रियता नहीं, बल्कि सपा की व्यापक रणनीति का एक अहम हिस्सा भी माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर आवाज जितनी ऊंची होती है, राजनीति उतनी ही अस्तरदार दिखाई जाती है। आरोप-प्रत्यारोप, तीखे बयान और मंचीय हमले यहां आम बात हैं। ऐसे माहौल में डिंपल की शैली अलग दिखाई देती है। यानि कम शोर, संयमित भाषा, सज्ज व्यवहार और टकराव की बजाय संवाद का अंदाज। यही वजह है कि सपा के लिए उनका चेहरा राजनीतिक रूप से उपयोगी हो सकता है। कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की राजनीति में धार वही है, लेकिन उसके साथ डिंपल की राजनीति का एक ‘साँपट टच’ जोड़ा जा रहा है।

यहीं से एक बड़ा सियासी सवाल निकलता है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं? फिलहाल सपा की राजनीति का केंद्रीय चेहरा अब भी अखिलेश यादव ही हैं। लेकिन राजनीति में हर बात की शुरुआत घोषणा से नहीं होती। कई बार किसी नेता की बढ़ती सक्रियता, बदलती भूमिका और सार्वजनिक स्वीकार्यता ही भविष्य के संकेत देने



लगती है। डिंपल की कार्यशैली अखिलेश से अलग है। अखिलेश जहां सीधे राजनीतिक हमले करने और भाजपा के खिलाफ आक्रामक विपक्षी राजनीति का चेहरा हैं, वहीं डिंपल अपेक्षाकृत शांत और संतुलित दिखाई देती हैं। उनकी यही अलग पहचान भविष्य में सपा के लिए एक अतिरिक्त राजनीतिक पूंजी बन सकती है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में अब कोई भी पार्टी महिलाओं को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। भाजपा अपनी महिला-केंद्रित योजनाओं और लाभार्थी राजनीति के जरिए महिला वोटरों पर लगातार पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रही है। दूसरी तरफ विपक्षी समझ चुका है कि सिर्फ जातीय समीकरणों से चुनावी लड़ाई पूरी नहीं होती। ‘आधी आबादी’ अब सिर्फ नारा नहीं, चुनावी समीकरण का बड़ा हिस्सा है। ऐसे में डिंपल यादव सपा के लिए एक प्रभावी महिला चेहरा बन सकती हैं। उनकी शांत और सहज छवि उन महिला मतदाताओं तक पहुंच बनाने में मदद कर सकती है, जो सपा को अब तक मुख्य रूप से पुरुष नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में देखती रही हैं। अगर पार्टी महिलाओं के लिए ठोस राजनीतिक कार्यक्रम और भरोसेमंद संदेश के साथ मैदान में उतरती है, तो डिंपल उस अभियान का स्वाभाविक चेहरा बन सकती हैं।

वैसे यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वह मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बनेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सपा को 2027 में महिला मतदाताओं के बीच अपनी नई जमीन तैयार करनी है, तो डिंपल की भूमिका केवल एक सांसद या स्टार प्रचारक तक सीमित नहीं रह सकती। यूपी की राजनीति में जो नेता धीरे-धीरे अपनी जूझ बनाता है, वह कई बार अचानक बड़े समीकरण का केंद्र बन जाता है। डिंपल के मामले में भी यही संभावना राजनीतिक चर्चा को दिलचस्प बनाती है।

अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि

2024 में बने राजनीतिक माहौल को 2027 की सत्ता तक पहुंचाने के लिए सिर्फ पुराने समीकरण काफी नहीं होंगे। दलित राजनीति की जमीन में बदलाव आया है, पिछड़ों के भीतर भी कई परतें हैं और सवर्ण मतदाताओं को लेकर नई राजनीतिक संभावनाएं तलाशनी पड़ रही हैं। यहीं से सामने आता है पीडीए का विस्तार। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए सपा की नई राजनीतिक रणनीति का केंद्र रहा है। लेकिन अब अखिलेश ने इस राजनीतिक फार्मूले में एक नया मोड़ दिया है। ‘पी’ की व्याख्या में पंडितों यानी ब्राह्मणों को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी भले बहुत बड़ी न हो, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव हमेशा संख्या से ज्यादा रहा है। गांव की चौपाल हो या शहर की राजनीतिक बैठक, कई इलाकों में ब्राह्मण मतदाता चुनावी माहौल और समीकरण दोनों पर असर डालता है। बसपा ने 2007 में दलित-ब्राह्मण सामाजिक समीकरण को मजबूत करके सत्ता का रास्ता बनाया था। बाद में भाजपा के उभार और नरेंद्र मोदी की राजनीति के साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ गए। अब अखिलेश उसी राजनीतिक जमीन में संभावनाएं तलाश रहे हैं।

अखिलेश यादव की राजनीति का एक और महत्वपूर्ण बदलाव हिंदू प्रतीकों को लेकर दिखाई देता है। वह अब केवल पुराने समाजवादी ढांचे में सिमटकर राजनीति नहीं करना चाहते। उन्हें मालूम है कि 2027 का उत्तर प्रदेश 1990 के दशक का उत्तर प्रदेश नहीं है। इसलिए सपा प्रमुख हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों से दूरी बनाने की बजाय उन्हें अपनी राजनीतिक भाषा का हिस्सा बना रहे हैं। सनातन धर्म की चर्चा, हनुमान चालीसा का पाठ, ब्राह्मणों तक पहुंच और धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी, यह सब एक व्यापक राजनीतिक संदेश का हिस्सा है। जनेश्व मिश्र की जयंती के मौके पर त्रिशूल और शिव स्तुति के बीच ब्राह्मणों तक पहुंचकर का संदेश इसी नई राजनीति की तस्वीर है। इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को भी इसी बड़े राजनीतिक संदर्भ में देखा जा सकता है। संदेश साफ है कि सपा सामाजिक न्याय की बात भी करेगी और हिंदू समाज के साथ संवाद भी बनाएगी। वैसे वह भाजपा के हिंदुत्व की सीधी नकल नहीं, बल्कि अपने लिए अलग राजनीतिक

जगह बनाने की कोशिश है।

लेकिन असली पेंच भी यही है। उत्तर प्रदेश में समीकरण बनाना आसान है मगर उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाना मुश्किल है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश में पीडीए का मूल आधार कमजोर नहीं हो। दूसरी चुनौती सपा की पुरानी राजनीतिक छवि है। भाजपा लगातार सपा के पिछले शासनकाल को कानून-व्यवस्था और कथित दबंग राजनीति के मुद्दे पर घेरती रही है। ऐसे में डिंपल यादव की बढ़ती भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका संयमित और सहज व्यक्तित्व सपा की छवि को नया आयाम दे सकता है। लेकिन यूपी की राजनीति में सिर्फ मुस्क्राहट से चुनाव नहीं जीते जाते। सवाल यह भी है कि क्या ब्राह्मण मतदाता वास्तव में भाजपा से दूर होंगे? क्या दलितों का बड़ा हिस्सा सपा की तरफ आएगा? क्या पिछड़ों के बीच पीडीए की पकड़ और मजबूत होगी? और क्या महिला मतदाता सपा को एक नए नजरिए से देखेंगे? सवाल यह भी है कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलकर समुच्च एक व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार कर पाएगी?

देखा जाये तो अखिलेश के सामने एक और चुनौती विपक्षी राजनीति के भीतर भी है। अगर सपा एक तरफ सवर्णों को जोड़ने की कोशिश करे और दूसरी तरफ उसके राजनीतिक सहयोगियों की भाषा उसी वर्ग को असहज करे, तो समीकरण बनने से पहले ही बिगड़ सकते हैं। यूपी में राजनीति का यही असली गणित है कि एक जाति को जोड़ो तो दूसरी की नाराजगी का डर, एक वर्ग को साधो तो दूसरे को संदेश देने की चुनौती। फिलहाल इतना साफ है कि अखिलेश यादव 2027 के लिए सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि समाजवादी पार्टी का नया संस्करण तैयार कर रहे हैं। उसमें पुराना समाजवाद है, नया पीडीए है, ब्राह्मणों के लिए जगह है, हिंदू प्रतीकों की स्वीकार्यता है और महिला मतदाताओं तक पहुंचने के लिए डिंपल यादव जैसा एक अलग चेहरा भी है। यहां सवाल उठता है कि क्या ‘शार्प’ अखिलेश और ‘साँपट’ डिंपल का यह राजनीतिक संतुलन 2027 में सपा के लिए नई ताकत बनेगा? या फिर उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति के पुराने गठ्ठे इस नई साइकिल की रफ्तार रोक देंगे? जवाब 2027 दिगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार साइकिल सिर्फ चलने नहीं, अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश में है।

हिंदी भाषा के उत्थान में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को कभी नहीं भूल सकते हैं

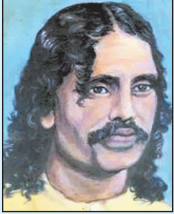
अकिंत सिंह

हिंदी साहित्य का आधुनिक काल प्रारंभ करने का श्रेय भी हरिश्चंद्र को ही जाता है। हिंदी पत्रकारिता नाट्य और काव्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान काफी रहा है। उन्हें उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार और ओजस्वी गद्यकार का दर्जा प्राप्त है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे। साहित्य में सोच की नींव रखने वाले अग्रणी साहित्यकार भारतेंदु

हरिश्चंद्र असाधारण प्रतिभा के धनी व दूरदर्शी युगचिंतक थे और उन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज में सार्थक हस्तक्षेप किया और इसकी शक्ति का उपयोग करते हुए आम जनमानस में जागृति लाने की

कोशिश की तथा दरबारों में कैद विधा को आम लोगों से जोड़ते हुए इसे सामाजिक बदलाव का माध्यम बना दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र कि आज 136वीं पुण्यतिथि है। उनका निधन महज 35 साल की उम्र में हो गया था। हिंदी की विपुल मात्रा और अनेक विधाओं से निपुण हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस दौर में हिंदी साहित्य के आयाम को नयी दिशा दी जब अंग्रेजों का शासन था और अपनी बात कह पाना कठिन था। उन्होंने एक ओर खड़ी बोली के विकास में मदद की वहीं अपनी भावना व्यक्त करने के लिए नाटकों और व्यंग्यों को बेहतरीन इस्तेमाल किया। इस क्रम में भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी जैसी उनकी कृतियों को देखा जा सकता है।



लिया और 34 साल के अपने जीवनकाल में ही उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध कर दिया। गौरीनाथ के अनुसार भारतेंदु ने साहित्य में सोच की नींव रखी और उस दौर की राजनीति में भी प्रतिरोध को दिशा दी। उनके लेखन से बाद की पीढ़ी को बल मिला। गौरीनाथ के अनुसार खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु की भूमिका उल्लेखनीय थी और वह सही मायनों में खड़ी बोली के सबसे बड़े निर्माता थे। उनकी रचनाओं में बनावटी संस्थागत कार्य के बदले प्रतिरोध का स्वर उभर कर सामने आता है। उनकी

अंधेर नगरी विशेष रूप से चर्चित हुई। कथाकार गौरीनाथ के अनुसार भारतेंदु के दौर में अपनी बात कहना बेहद कठिन था। विदेशी शासन के प्रति अपने प्रतिरोध को जताने के लिए उन्होंने साहित्य का सहारा

कृतियों में उस दौर की स्थित, समिस्याएं उभर कर सामने आती हैं और वह परोक्ष रूप से उसके प्रति लोगों को आगाह करते दिखते हैं।

भारतेंदु के लेखन में परोक्ष रूप से आजादी का स्वप्न और भविष्य के भारत की रूपरेखा की झलक मिलती है। वह धार्मिक एकता व प्रांतीय एकता के भी पक्षधर थे। धार्मिक एकता की जरूरत का जिक्र करते हुए भारतेंदु ने अपने एक भाषण में कहा था कि घर में जब आग लग जाए तो देवरानी और जेठानी को आपसी डाह छोड़कर एक साथ मिलकर घर की आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। उनकी नजर में अंग्रेजी राज घर की आग के समान था और देवरानी जेठानी के संबंध जिस प्रकार प्रचारविराक एकता के लिए अहम है, उसी प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता की भावना राष्ट्रीय आवश्यकता है।

आज का इतिहास

- 1776 अमेरिकी संसद कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम यूनाइटेड कॉलोनीज़ से बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका किया।
- 1850 कैलीफ़ोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य बना।
- 1867 यूरोपीयीय देश लक्जमबर्ग ने स्वतंत्रता हासिल की।
- 1915 प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी सचिन्द्रनाथ सान्याल और अंग्रेज़ों के बीच उड़ीसा के काटेवाड़ा में संघर्ष।
- 1920 अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रूपांतरित हो गया।
- 1924 9 सितंबर से 11 सितंबर तक भारत में कोहाट दंगे हुए।
- 1949 भारत की संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।
- 1976 माओ त्से तुंग का देहावसान एवं कुओ फ़ेंग राष्ट्रपति बने।
- 1939 द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नाजी सेना वर्साय पहुँची।
- 1954 अफ़्रीकी देश अल्जीरिया में भूकंप से 1400 लोग मरे।
- 1965 तिब्बत चीन का स्वायत्त क्षेत्र बना।
- 1967 गुग्रांड ब्रिटेन से आज़ाद हुआ।
- 1979 जोगेन्द्रनाथ हज़ारिका ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया।
- 1991 तज़ाकिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता हासिल की।
- 1998 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की प्रकरण पर स्वतंत्र वकील केनेथ स्टार ने अपनी बहुवर्चित रपट कांग्रेस को प्रेषित किया।
- 1999 भारत के महेश भूपति तथा जापान की आर्क सुगियामा की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का मिश्रित युगल ख़िताब जीता।
- 2001 वीनस विलियम्स ने छोटी बहन सेरेना को ग्रैंडस्लैम फ़ाइनल में हराया।
- 2002 पीट सम्प्रास ने आंद्रे अगासी को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस ख़िताब जीता।
- 2004 फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री अहमद कु़रेई ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया।
- 2005 चीन के बीजिंग स्थित छाओयांग पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण।
- 2006 अंतर्राष्ट्रीय दबाव के मद्देनज़र इराक़ल द्वारा आठ सप्ताह से की गुपी लेबनान की नौसैनिक घेराबन्दी को समाप्त किया गया।
- 2007 वेनिस फ़िल्म फ़ेस्टिवल में हॉलीवुड एक्टर ब्रेड पिट को बेस्ट एक्टर का तथा केट ब्लैंशट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया।
- हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार तथा लोकवार्ताकार डॉ.अर्जुनकेश केशरी को साहित्य महोपाध्याय अलंकरण प्रदान करने की घोषणा की गई।

पायलट आखिर कैसे पंजाब कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे?

नीरज कुमार दुबे

राजस्थान में एक समय बगावत का रायता फैलाने वाले सचिन पायलट आखिर पंजाब कांग्रेस को एकजुट कैसे रख पाएंगे ? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खुली जंग का खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ा था। विडंबना देखिए, उस समय पंजाब के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं तथा चन्नी गुट के साथ खड़े हैं। ऐसे में पायलट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो नेता अपने गृह प्रदेश में गुटबाजी की आग को नहीं बुझा पाया, वह पंजाब में बिखरी कांग्रेस को कैसे एकजुट करेगा ?

हम आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट को भूपेश बघेल की जगह पंजाब का प्रभारी बनाकर भेजा है। भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस के पास अंदरूनी कलह

सुलझाने के लिए बहुत अधिक समय नहीं है। ऐसे में 49 वर्षीय सचिन पायलट की नियुक्ति को कांग्रेस की ओर से एक बड़े राजनीतिक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि राजस्थान का कभी का ‘बागी’ क्या अब पंजाब में ‘शांतिदूत’ की भूमिका निभा पाएगा ?

देखा जाये तो सचिन पायलट का अपना राजनीतिक इतिहास इस जिम्मेदारी को और दिलचस्प बनाता है। 2014 में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संगठन को खड़ा किया और 2018 में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सत्ता मिलते ही अशोक गहलोत और पायलट के बीच नेतृत्व, संगठन और राजनीतिक भविष्य को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। जुलाई 2020 में यह संघर्ष खुली बगावत में बदल गया। पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग हो गए, राज्य सरकार संकट में आई और उन्हें उपमुख्यमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।

सचिन पायलट ने तब भाजपा में जाने से साफ इंकार किया था और कहा था कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं, बल्कि गहलोत से है। वह कांग्रेस में रहे, लेकिन गहलोत-पायलट की प्रतिद्वंद्विता वर्षों तक पार्टी के लिए सिरदर्द बनी रही। बाद में सार्वजनिक



तौर पर रिश्तों में नरमी दिखाई गई।

2025 में गहलोत ने यहां तक कहा कि हम कब अलग थे? लेकिन राजनीतिक इतिहास इतनी आसानी से मिटता नहीं। पायलट और गहलोत के बीच मतभेद खत्म होने के दावे के बावजूद समय-समय पर दोनों खेमों की दूरियां सामने आती रही हैं। यही नहीं, 2028 में होने

वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले गहलोत-पायलट की प्रतिस्पर्धा फिर तेज हो सकती है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जिस नेता ने अपने ही प्रदेश में मजबूत राजनीतिक गुट खड़ा किया और गुटबाजी को हवा दी, वह दूसरे प्रदेश में गुटबाजी खत्म करने का कौन-सा सफल फार्मूला

अपनाएगा ? हालांकि पंजाब में पायलट के अनुभव का दूसरा पहलू भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वयं देखा है कि अनसुलझी नेतृत्व की लड़ाई किसी राज्य इकाई को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। शायद इसी अनुभव के कारण हाईकमान उन्हें एक ‘ऑर्गेनाइजेशनल फिक्सर’ के तौर पर

आजमा रहा है।

उधर, पंजाब कांग्रेस में संकट गंभीर है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाला एक गुट राजा वारिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग करता रहा है। हाईकमान ने जुलाई में वारिंग को पद पर बनाए रखा और चन्नी को चुनाव अभियान समिति की कमान दी, लेकिन इससे असंतोष खत्म नहीं हुआ। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं बताए जाते। सुखजिंदर सिंह रंधावा और विजय इंदर सिंगला जैसे नेता भी वारिंग विरोधी खेमे में रहे हैं।

भूपेश बघेल इस खींचतान को खत्म नहीं कर पाए। उन पर वारिंग के ज्यादा करीब होने और निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने के आरोप लगे। उनके खिलाफ पंजाब के कुछ इलाकों में पोस्टर तक लगाए गए। अब पायलट की नियुक्ति को वारिंग विरोधी नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिश माना जा रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि वारिंग, चन्नी और रंधावा, सभी ने पायलट की नियुक्ति का स्वागत किया है। लेकिन असली परीक्षा स्वागत संदेशों से नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या चन्नी वारिंग को हटाने की मांग छोड़ेंगे ? क्या बाजवा, रंधावा और अन्य वरिष्ठ नेता एक मंच पर वास्तविक रूप से साथ

आएंगे ? इसके साथ ही राहुल गांधी का प्रस्तावित पंजाब बस दौरा, सचिन पायलट की पहली बड़ी परीक्षा हो सकता है।पायलट को केवल नेताओं की बैठकें नहीं करानी होंगी। उन्हें गुटों के बीच भरोसा पैदा करना होगा, टिकट वितरण को नए संघर्ष का कारण बनने से रोकना होगा और महत्वाकांक्षी नेताओं को समझाना होगा कि एक-दूसरे को कमजोर करने से अधिक नुकसान कांग्रेस का होगा।

2027 में कांग्रेस का मुकाबला भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार से है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठजोड़ से मुकाबला और जटिल हो सकता है। क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतें भी समीकरण बदल सकती हैं। इसलिए पंजाब सचिन पायलट के लिए महज एक नई जिम्मेदारी नहीं है। यह उनकी राजनीतिक परिपक्वता की सबसे कठिन परीक्षा है। राजस्थान में वह कभी कांग्रेस के भीतर बगावत का चेहरा बने थे, पंजाब में उन्हें समझौते और एकजुटता का चेहरा बनना है। देखना होगा कि क्या पायलट अपने अतीत से सबक लेकर पंजाब कांग्रेस को जोड़ पाएंगे, या पंजाब की गुटबाजी साबित करेगी कि कांग्रेस के भीतर कुछ दरारें इतनी गहरी हैं जिन्हें कोई भी प्रभारी भर नहीं सकता ?

ब्रिक्स में क्या खेला करने भारत आ रहे रूस, चीन और ईरान

अभिनय आकाश

ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। बहुत बड़ी बैठक इसी महीने नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। दुनिया की नजरें ब्रिक्स की बैठक पर है। 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता में बैठक कर रहा है, वो कहां करने वाला हे ? ये नई दिल्ली में भारत मंडपम में 12 13 सितंबर को ब्रिक्स देशों की बैठक होगी और इसके लिए पहले भी साल भर वकिंग ग्रुप्स हैं, मंत्रियों स्तर की बैठक है, सीजीआई स्तर की बैठक है, बैंकिंग स्तर की बैठक है, एनएसए लेवल की बैठक है। ये सब कुछ पहले ही भारत में हो चुका है। और अब राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच यह बैठक 12 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। ब्रिक्स उभरते हुए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले 11 प्रमुख देशों का एक रूप है जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात है। ये जो ब्रिक्स है इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये जो ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय, राजनीतिक और आर्थिक गवर्नेंस से जुड़े मामलों पर लगातार बातचीत करता है। और सहयोग के लिए एक अहम मंच है और यही वजह है कि ब्रिक्स का जब भी नाम आता है तो अमेरिका की धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ब्रिक्स के जरिए डॉलर को धराशायि करने का प्लान है और डॉलर को ठेगा दिखा के अगर ब्रिक्स देश आपस में ही कोई अपनी करेंसी बना ले कोई अपना ट्रांज़ेक्शन सिस्टम बना ले तो अमेरिका को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसके लोगों में भारत के राष्ट्रीय फूल कपल है। इसके बीच में नमस्ते की मुद्रा है। इसे एक पब्लिक डिजाइन प्रतियोगिता के जरिए चुना गया। उन्होंने पंखुड़ियों में ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों का रंग है जो इसकी आधिकारिक थीम से जुड़े हुए हैं। मजबूत इन्ोवेशन, सहयोग और सेंसबिलिटी का निर्माण। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन का है जिनका आना लगभग

तय माना जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिजिंगपिंग के भी दौरे की जानकारी है कि वो भी इस दौरे पर आ सकते हैं। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियान भी भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। यानी कि तीन अहम राष्ट्रपति भारत जो हैं वैश्विक नेता जो हैं वह भारत में ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस बार नई दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है। यह सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब मध्य पूर्व और यूरोप में जो है वो युद्ध के कारण भू राजनीतिक तनाव जो है वो अपने चरम पर है और अमेरिका को लेकर भी बहुत उथल-पुथल है। इसके अलावा माना जा रहा है कि अब जो है समूह का विस्तार जो है वो एशिया, अफ्रीका, मध्यपूर्व और लैटिन अमेरिका तक हो गया है। उम्मीद है कि इस पूरे ब्लॉक के नेता और वरिष्ठ प्रतिनिधि भी आपको एक साथ नजर आएंगे। सम्मेलन के लिए बताया जा रहा है कि नई दिल्ली आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों में जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी शामिल हो सकते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अलसीसी भी शामिल हो सकते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी आ सकते हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोरमाट टोकयो भी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबान्तो भी शामिल हो सकते हैं। मान जानकारी यह भी है कि मलेशिया, थाईलैंड, इथोपिया के भी पीएम जो हैं वह इस शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। जबकि क्यूबा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधि जो है उनके राष्ट्रपतियों के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा माना जा रहा है कि कई अहम देशों के मंत्री जो हैं अह वो घरेलू व्यवस्थाओं में जो है लूला डिसिलवा शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा युगांडा का प्रतिनिधित्व मंडल आएगा। वहीं वियतनाम के पीएम जो आ सकते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि भी हैं वो अबू धाबी के काउंस प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़द अल नहायन कर सकते हैं।

अरुणिम भूयान

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की श्रीलंका यात्रा उनके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिणी पड़ोसी के साथ भारत के जुड़ाव में एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि दशकों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की इस द्वीप राष्ट्र की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक उच्च-स्तरीय मुलाकात से कहीं बढ़कर है।

8 से 10 सितंबर तक होने वाला यह दौरा हिंद महासागर में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच दोनों देशों के रिश्तों में रक्षा और समुद्री सुरक्षा को मुख्य केंद्र में रखने के नई दिल्ली के इरादे की दर्शाता है। रविवार को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध और एक बहुआयामी साझेदारी है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक व व्यापार सहयोग और मजबूत जन-संबंधों पर आधारित है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को तब और गति मिली जब भारत ने आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका की मदद की और 2025 में श्रीलंका में आए चक्रवात डिटवा के बाद सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में से एक रहा। इसने पड़ोसी पहले की नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महासागर (MAHASAGAR – क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) के दृष्टिकोण के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

मंत्रालय ने कहा कि सिंह की श्रीलंका यात्रा एक मजबूत समुद्री और रक्षा साझेदारी सहित पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से मजबूत



और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी।

इस यात्रा का समय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। श्रीलंका हिंद महासागर में कुछ सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बीच एक बेहद अहम स्थान पर है, जबकि भारत अपनी पड़ोसी पहले की नीति और मोदी के महासागर दृष्टिकोण के तहत पूरे क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारियों के अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है। इसलिए, सिंह की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत की समुद्री सुरक्षा के लिहाज से श्रीलंका का रणनीतिक महत्व काफी बढ़ गया है।

दशकों में किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री ने श्रीलंका का दौरा नहीं किया है। श्रीलंका के गृहयुद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान, जब द्वीप पर हो रहे घटनाक्रमों से भारत के सुरक्षा और राजनीतिक हित सीधे जुड़े थे, तब 2008 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के। एंटनी की यात्रा पर विचार किए जाने की खबर थी। हालांकि, एंटनी ने श्रीलंका की यात्रा नहीं की थी। इसके बजाय, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव और रक्षा सचिव ने कोलंबो का दौरा किया था।

इसलिए, राजनाथ सिंह की यह यात्रा एक लंबे अंतराल के बाद रक्षा-मंत्री स्तर के राजनीतिक जुड़ाव की बहाली को दर्शाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सिंह सितंबर 2023 में श्रीलंका की यात्रा पर जाने

वाले थे, लेकिन बाद में उस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। साल 2022 में श्रीलंका द्वारा झेले गए गंभीर आर्थिक संकट के बाद से भारत और श्रीलंका के संबंधों में काफी बड़ा बदलाव आया है।

जब श्रीलंका ईंधन, भोजन, दवाओं और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा था, तब भारत ने उसे बड़े पैमाने पर आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान की थी। उस सहायता ने नई दिल्ली के प्रति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सद्भावना स्थापित करने में मदद की और अपने निकटतम पड़ोस में सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देश के रूप में भारत की छवि को और मजबूत किया।

इसके बाद दोनों देशों के संबंधों को एक मजबूत रणनीतिक आयाम मिला। रक्षा और समुद्री सहयोग द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण हिस्से बन गए हैं, जिसमें भारत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, सैन्य अभ्यास, उपकरण और संस्थानगत आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

राजनाथ सिंह की चर्चाओं में शामिल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक अप्रैल 2025 में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन होने की संभावना है। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यापक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। इसका महत्व द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को व्यक्तिगत अभ्यासों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उपकरण सहायता से आगे बढ़ाकर एक अधिक संरचित साझेदारी की ओर ले जाने में है।

दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच रक्षा बलों के प्रमुखों के दौरों के माध्यम से उच्च स्तरीय रक्षा जुड़ाव नियमित रहा है। इसके अलावा, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा करने और उसे गति देने के लिए हर साल रक्षा सचिवों के बीच एक वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की जाती है।

चीन से मिले सबक के बाद भारत की ओर क्यों रुख कर रहा यूरोप?

निर्मला गणपति

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा कि चीन पर अत्यधिक व्यापारिक निर्भरता के कारण यूरोप को कड़ा सबक मिला है, और उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के नेताओं को इस संभावना के बारे में चेतावनी दी थी।भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए डी वेवर ने एक व्यापारिक कार्यक्रम में बोलते हुए चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसे एक ऐसा पड़ोसी जिसे आप सभी जानते हैं कहकर संबोधित किया।

उन्होंने कहा, बहुत लंबे समय तक यूरोप देखता रहा कि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को हमारे बाजार में लागत से कम दाम पर बेचा जा रहा है, हमारे औद्योगिक आधार को कमजोर किया जा रहा है और जानबूझकर निर्भरताएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि उनका इस्तेमाल लाभ उठाने के लिए किया जा सके। उन्होंने आगे कहा, इससे सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला देश यहां से ज्यादा दूर नहीं है। यह एक ऐसा पड़ोसी है जिसे आप सभी जानते हैं। भारत ने इसे हमसे पहले ही देख लिया था। और उन्होंने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा, यूरोप अब सुन रहा है। हम भी अब सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापारिक तनाव के मद्देनजर, भारत और यूरोप के बीच तालमेल बढ़ रहा है क्योंकि दोनों पक्ष एक-दूसरे को परीसेमंद साझेदार के रूप में देखते हैं।

बेल्जियम के प्रधानमंत्री की व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता संबंधी टिप्पणियां सस्ते चीनी सामानों के आयात से यूरोपीय विनिर्माण पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर यूरोपीय देशों में बढ़ती चिंता को दर्शाती हैं। यूरोप वर्षों से चीन से किरावटी विनिर्माण वस्तुओं के आयात पर निर्भर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ तो हुआ है, लेकिन स्थानीय विनिर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

वस्तुओं की डीपिंग एक चिंता का विषय है। डीपिंग तब होती है जब किसी उत्पाद का आयात उस देश के बाजार में उत्पादन लागत से कम कीमत पर किया जाता है।परिणामस्वरूप, यूरोपीय संघ को चीन के पक्ष में प्रतिदिन लगभग एक अरब यूरो के भारी व्यापार घाटे का



सामना करना पड़ रहा है।यूरोपीय संघ के आंकड़ों के अनुसार, व्यापार घाटा सालाना 360 अरब यूरो है, जिसमें चीन से आयात 559।4 अरब यूरो और यूरोपीय संघ का निर्यात 199।6 अरब यूरो है।

अमेरिका और ब्रिटेन के बाद चीन यूरोपीय संघ का वस्तुओं और सेवाओं का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2025 में यूरोपीय संघ द्वारा आयातित निर्मित वस्तुएं चीन से होने वाले कुल आयात का 97।3 प्रतिशत थीं।पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, चीन पर निर्भरता इतनी अधिक है कि सस्ते चीनी आयात से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होने के कारण यूरोपीय संघ के रसायन और कार निर्माता कारखाने बंद कर रहे हैं और कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं।चीन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के इस्पात उद्योग और दवा उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं।

इसके जवाब में, ब्रसेल्स वीजिंग के साथ व्यापार समझौते पर बाधचीत कर रहा है और चीन से व्यापार घाटे को कम करने और यूरोपीय कंपनियों के लिए बाजार खोलने की प्रतिबद्धता की मांग कर रहा है।यूरोपीय संघ अक्टूबर तक व्यापार वार्ता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा न होने पर उसने संभावित व्यापारिक उपायों की चेतावनी दी है।व्यापार युद्ध का खतरा बना हुआ है क्योंकि वीजिंग ने चेतावनी दी है कि वार्ता एकतरफा मांगों के आधार पर नहीं चलाई जा सकती।

बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भले ही यह स्पष्ट न किया हो कि मोदी ने यूरोप को चीन के खिलाफ कब चेतावनी दी थी, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर

आर्थिक निर्भरता को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के खतरे के प्रति आगाह किया है।पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को उजागर किया है और विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के महत्व पर जोर दिया है।

यूरोप की तरह, भारत को भी चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे की दीर्घकालिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उसने इस खतरे को शुरूआत में ही पहचान लिया था।भारत ने विनिर्माण प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जांच और डीपिंग-विरोधी शुल्कों के माध्यम से अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करने का प्रयास किया है।

इसके बावजूद, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता रहा है, जो 2025-2026 में रिकॉर्ड 112।16 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष के 99।2 अरब डॉलर से अधिक है।एक ओर अमेरिका की अप्रत्याशित टैरिफ नीतियों और दूसरी ओर चीन की औद्योगिक अतिरिक्त क्षमता के बीच फंसा यूरोप तेजी से भारत की ओर देख रहा है।

भारत और यूरोपीय संघ ने लगभग दो दशकों के बाद इस वर्ष जनवरी में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को अगले वर्ष की शुरुआत में लागू किए जाने की संभावना है। अमेरिका और चीन के बीच फंसे यूरोप के लिए, यह समझौता व्यापार साझेदारों में विविधता लाने और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण को एक नई रणनीति को रेखांकित करता है।

भारत-बेल्जियम संबंधों का विस्तार – यह कोई संयोग नहीं है कि डी वेवर की भारत यात्रा दो दशकों में किसी बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के साथ संबंध स्थापित करने में यूरोपीय देशों की नवप्रवर्तित रुचि को रेखांकित करता है।परंपरागत रूप से, भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार एंटरप्रा से होने वाले हिरे के व्यापार पर आधारित रहा है।लेकिन अब संबंधों को इससे आगे बढ़ाकर रक्षा और आर्थिक सहयोग तक विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सात चुनाव से किशनी में सपा का दबदबा

अमन तिवारी

उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर चुनावी मोड़ में नजर आने लगी है। यहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सियासी दल जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। आने वाले चुनाव में जहां भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष सत्ता परिवर्तन की उम्मीदों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में हम आपको यूपी की सभी विधानसभा सीटों का इतिहास, राजनीतिक सफर और चुनावी गणित बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज चर्चा मैनपुरी जिले की किशनी विधानसभा सीट की। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनमें कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इन्हीं में से एक जिला मैनपुरी है। मैनपुरी जिले में कुल चार विधानसभा सीटें हैं। इनमें– मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल शामिल हैं। सीट का समीकरण की आज की कड़ी में हम मैनपुरी जिले की किशनी विधानसभा सीट की बात करेंगे। मैनपुरी जिले की किशनी विधानसभा सीट पहली बार वर्ष 1961 के परिसीमन आदेश के बाद अस्तित्व में आई थी और यहां पहला विधानसभा चुनाव 1962 में हुआ था। किशनी विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं में सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति और क्षत्रिय समुदाय की है, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 14–14% है। इसके बाद यादव मतदाताओं की एक मजबूत आबादी लगभग 13% है, जो चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं शाक्य (कुशवाहा) समाज की हिस्सेदारी करीब 10% और मुस्लिम मतदाता लगभग 6% हैं। इनके अलावा ब्राह्मण समाज के करीब 5%, लोधी समुदाय के लगभग 4% तथा वैश्य वर्ग के करीब 3% मतदाता मौजूद हैं। बाकी बचे मतदाता अन्य अति पिछड़े और सर्वण समुदायों से आते हैं। 1962 के चुनाव में किशनी विधानसभा सीट के पहले चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गणेश चंद्र विजयी

हुए। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चिरंजी लाल को 4,812 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में गणेश चंद्र को 11,363 वोट मिले, जबकि चिरंजी लाल को 6,551 वोट मिले। 1996 के विधानसभा चुनाव में किशनी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के रामेश्वर दयाल बाल्मीकि विजयी हुए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सय्याम शरण को 20,197 वोटों के भारी अंतर से हराया। इसके बाद आगे चुनाव में सपा ने अपना चेहरा बदला और 2002 में संध्या कठेरिया को मैदान में उतारा। संध्या कठेरिया ने 2002 में भाजपा के रामेश्वर दयाल बाल्मीकि को 14,559 वोटों से हराकर किशनी में सपा का कब्जा बरकरार रखा। 2007 में भी उन्होंने अपनी जीत दोहराई। इस बार बसपा के सुनील कुमार उनके सामने थे, जिन्हें संध्या ने 5,603 वोटों से मात दी। लगातार दो चुनाव जीतने के साथ सपा ने किशनी को अपने मजबूत राजनीतिक आधार में बदलना शुरू कर दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने किशनी में एक बार फिर अपना चेहरा बदला। इस बार इंजी. बृजेश कठेरिया को मैदान में उतारा गया। उन्होंने बसपा की संध्या को 35,050 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट अपने नाम कर ली। चुनाव में बृजेश कठेरिया को 77,113 वोट मिले, जबकि संध्या को 42,063 वोट मिले। 2012 के बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में किशनी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के बृजेश कुमार विजयी हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार को 16,529 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में बृजेश कुमार को 80,475 वोट मिले, जबकि सुनील कुमार को 63,946 वोट मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव में किशनी की लड़ाई और दिलचस्प हो गई। सपा ने एक बार फिर इंजी. बृजेश कठेरिया पर भरोसा जताया, जबकि भाजपा ने डॉ. प्रिया रंजन आशु दिवाकर को मैदान में उतारा। बृजेश कठेरिया ने भाजपा की चुनौती को पीछे छोड़ते हुए 19,151 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में युवा सशक्तीकरण को नई दिशा

युवा शक्ति से आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की नई उड़ान

कौशल, नवाचार, रोजगार और स्वरोजगार के जरिए बदल रही युवाओं की तकदीर

छत्तीसगढ़ आज युवा शक्ति के दम पर विकास की नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि अवसरों का निर्माण करने वाला नागरिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, स्टार्टअप प्रोत्साहन, उद्योगों से साझेदारी, स्वरोजगार योजनाएं और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएं मिलकर एक ऐसे आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की नींव रख रही हैं, जहां हर युवा के सपनों को उड़ान देने का प्रयास किया जा रहा है।

“हमारा लक्ष्य केवल युवाओं को प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ का प्रत्येक युवा अपनी प्रतिभा और कौशल के बल पर सफलता प्राप्त करे, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। युवा शक्ति ही विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत है।

- विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



नांदी फाउंडेशन, महिंदा एंड महिंदा, मेस्कॉम जैसे संस्थानों के साथ MOU से युवाओं को आधुनिक तकनीकी, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के नए अवसर मिल रहे हैं।

कौशल विकास: सफलता की नई पहचान

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं, ग्रामीणों, निर्माण श्रमिकों और विशेष वर्गों को निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रमाण-पत्र, प्लेसमेंट सहायता और उद्योगों से जुड़ाव की व्यवस्था की जा रही है। हर्ष साहू (राजनांदगांव), आकांक्षा कुशवाहा (दुर्ग) और आशीष कुमार पटेल (दुर्ग) जैसे हजारों युवा प्रशिक्षण पाकर रोजगार से जुड़े और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं।

उद्योगों से साझेदारी, प्रशिक्षण का विस्तार



‘कौशल तिहार’ युवाओं की प्रतिभा को नई पहचान दे रही है। राज्य स्तर पर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, ग्राफिक डिजाइन, नवीकरणीय ऊर्जा, हेल्थ केयर तथा रेफ्रिजरेशन जैसे प्रमुख ट्रेड शामिल किए गए हैं।

प्रशिक्षण से रोजगार तक का मजबूत सेतु

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से आधुनिक उद्योगों के अनुरूप युवाओं को दक्ष बनाया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों, पुनर्वास केंद्रों और आत्मसमर्पित युवाओं को भी प्रशिक्षण के अवसर मिल रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति फेस रिकनिशन आधारित प्रणाली से दर्ज की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

शिक्षा, नवाचार, स्टार्टअप का नया दौर



आधुनिक आईटीआई, लाइलीवुड कॉलेज, AI, रोबोटिक्स, ई-डब और स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रमों से युवा नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं। 5,000 स्टार्टअप का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा तय करेगा।

स्वरोजगार से आर्थिक सशक्तीकरण



CMEGP, PMEGP और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग, सेवा और व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण, अनुदान, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है। मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, मसाला जैसे हजारों सूक्ष्म उद्योग विकसित हो रहे हैं।

उद्योगों से साझेदारी, प्रशिक्षण का विस्तार



महिंदा एंड महिंदा के सहयोग से दत्तेवाड़ा, बलरामपुर और कोडगांव में ट्रेक्टर मैकेनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल रहे हैं।

पारदर्शी भर्ती से बढ़ा युवाओं का विश्वास



PSC परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिमित करने के लिए सख्त कदम उठाये गए हैं। प्रयोगशाला परिचारक सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र देकर हजारों युवाओं के सपनों को नई दिशा दी गई है।

कुटीर उद्योगों से गांवों में समृद्धि



खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से महुआ, इमली, साल आदि वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर विकसित किए जा रहे हैं।

सुशासन फेलोशिप : नीति निर्माण में भागीदारी



नवंबर 2024 में शुरू मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप युवाओं को प्रशासन और नीति निर्माण से जोड़कर विकास योजनाओं में योगदान का अवसर प्रदान कर रही है। आईआईएम रायपुर के सहयोग से कार्यक्रम संचालित।

विकास के नए द्वार, भविष्य की मजबूत आधारशिला



नई औद्योगिक नीति 2024-30, बड़े निवेश प्रस्ताव, मेडिसिटी, फिल्म सिटी, IT, AI, फार्मा, एग्रो प्रोसेसिंग और पर्यटन परियोजनाओं से लाखों रोजगार अवसर सृजित होंगे। बस्तर और सरगुजा में होम स्टे, वन उत्पाद आधारित उद्योग और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

नई पीढ़ी, नया विश्वास, नया छत्तीसगढ़

युवा शक्ति ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार की योजनाएं युवाओं को हुनर, संसाधन, अवसर और आत्मविश्वास प्रदान कर रही हैं। रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक कौशल से लेकर नवाचार तक और शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक, हर क्षेत्र में युवा परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं। यही युवा शक्ति आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की सबसे मजबूत आधारशिला सिद्ध होगी।



शिक्षा
सशक्तीकरण



तकनीकी
शिक्षा



नवाचार और
स्टार्टअप



उद्योगों से
साझेदारी



रोजगार और
स्वरोजगार



युवा सशक्त
छत्तीसगढ़

युवा उपलब्धियां



8.43 लाख

युवाओं को
प्रशिक्षण



2.66 लाख

से अधिक युवाओं
को रोजगार



5000

स्टार्टअप विकसित
करने का लक्ष्य



कौशल तिहार

2025 से हुनर
को नई पहचान



विश्व रिकल्स
2026, शंघाई
में भारत का
प्रतिनिधित्व



मुख्यमंत्री

सुशासन फेलोशिप
नवंबर 2024



आधुनिक
आईटीआई AI,
रोबोटिक्स और
डिजिटल शिक्षा



उद्योगों से
साझेदारी और
MOU, के जरिए
रोजगार के अवसर



पारदर्शी भर्ती से
युवाओं का
विश्वास और
मजबूत

सहकारिता मंत्री ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

को-ऑपरेटिव बैंको में भर्ती जल्द हो: मंत्री कश्यप

रायपुर। सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। मंत्री श्री केदार कश्यप ने बैठक में सहकारिता के सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और किसान-हितैषी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारा मुख्य ध्येय प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माध्यम से अंतिम व्यक्ति और प्रदेश के प्रत्येक किसान तक शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।

बैठक में मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि डिजिटलाइजेशन और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं से किसानों का भरोसा सहकारिता प्रणाली पर और मजबूत होगा। उन्होंने को-आपरेटिव बैंको में रिक पदों की समीक्षा की। उन्होंने रिक पदों की भर्ती की कार्यवाही तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने सहकारी सप्ताह 29 जून से 06 जुलाई 2026 तक छत्तीसगढ़ में को-



ऑपरेटिव सेक्टर में आयोजित विविध कार्यक्रम पर केन्द्रीय काफी-टेबल बुकलेट का विमोचन किया गया।

बैठक में मंत्री कश्यप ने अधिकारियों, प्रबंध संचालकों, संभागीय संयुक्त आयुक्तों, उप/सहायक आयुक्तों तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटराइजेशन और अंकेक्षण (ऑडिट) प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रहे।

7973 करोड़ रुपए का ऋण वितरित

मंत्री श्री कश्यप ने अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान, समय पर उर्वरक (खाद), बीज एवं ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को कोआपरेटिव बैंको के माध्यम से चालू खरीफ सीजन 2026 हेतु 8800 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को 7973 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 90 प्रतिशत है। बैठक में मंत्री श्री कश्यप द्वारा अधिकारियों को

शत-प्रतिशत कृषि ऋण वितरण के निर्देश दिया गया। ग्रामीण अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार करने तथा माइक्रो ए.टी.एम. की उपलब्धता बढ़ाकर डिजिटल बैंकिंग को सुलभ बनाने पर बल दिया गया।

718 गोदामों का निर्माण पूर्ण

100 सोसायटियों में गोदाम निर्माण व त्वक्थ योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही नवगठित 515 पैक्स के सुचारू संचालन के निर्देश दिए गए। बैठक में आराईडीएफ अंतर्गत आबंटित 725 गोदामों में 718 गोदामों के निर्माण पूर्ण होने की जानकारी दी गई है। शेष 7 गोदाम के जल्द ही निर्माण पूर्ण किये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा कार्यालयों में ई-ऑफिस और आधार-बेस्ड उपस्थिति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए।

महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में 34 प्रकरणों पर सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में आज आयोग कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई आयोजित की गई। प्रदेश स्तर पर यह आयोग की पांचवीं तथा रायपुर जिले में चौथी



जानसुनवाई थी। सुनवाई हेतु कुल 34 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें 23 प्रकरणों की सुनवाई की गई तथा 08 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए।जानसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रकरणों में आवेदिकाओं की शिकायतों एवं संबंधित पक्षों के कथनों को विस्तारपूर्वक सुना गया। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण एवं जान से मारने की धमकी से संबंधित प्रकरण में आयोग द्वारा संबंधित थाना को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।पति द्वारा मानसिक प्रताड़ना, दूसरी महिला के साथ रहने तथा पत्नी एवं पुत्री को भरण-पोषण नहीं दिए जाने के प्रकरण में आवेदिका को न्यायालय के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई। प्रकरण के समुचित निराकरण तक इसकी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में अनावेदक की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण में पुलिस अधीक्षक रायपुर को प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विवाद की स्थिति को देखते हुए पृथक-पृथक किराये के आवास में रहने के निर्देश दिए गए।

पैसे लेकर कांग्रेस की सदस्यता देने को लेकर श्रीवास्तव का तीखा हमला संगठन की सदस्यता में भी भ्रष्टाचार, यही है कांग्रेस के डीएनए की सच्चाई : संजय श्रीवास्तव

रायपुर। यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में पैसे लेकर सदस्यता देने का मामला सामने आने पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता "श्री संजय श्रीवास्तव" ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।



के लिए यह आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि "कांग्रेस देश में 58 वर्षों तक सत्ता

में रही है। उनके इतने लंबे शासनकाल में उनके बड़े-बड़े नेताओं की भ्रष्टाचार और घोटालों के कई मामलों में सल्लिखन के सबूत मिले हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराब घोटाले, कोयला घोटाले और डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर भ्रष्टाचार की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस जैसे संगठन में सदस्यता ही चुनावी प्रक्रिया का आधार होती है। जब सदस्यता के आधार पर संगठन के भीतर चुनाव होते हैं, तब सदस्य बनाने के लिए ही पैसे लिए जाने के

आरोप लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पागदरिश्ता पर सवाल खड़े करते हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि "यदि किसी राजनीतिक दल में सदस्यता से लेकर चुनाव तक पैसे का प्रभाव दिखाई देने लगे, तो यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि यूथ कांग्रेस की सदस्यता प्रक्रिया में पैसे लिए जाने के आरोपों की सच्चाई क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज देश के लिए नासूर बन चुकी है और जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आते रहते हैं।

श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि "कांग्रेस को अपने संगठन के भीतर झांककर देखना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि आखिर उसकी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यप्रणाली पर बार-बार भ्रष्टाचार के सवाल क्यों उठते हैं।"

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार



यूसीसी का सर्वे, सुझाव मात्र दिखावा है : दीपक बैज

रायपुर। यूसीसी के नाम पर 'सर्वसमावेशी सुझाव और सर्वे' के दावों को केवल आईवांश (दिखावा) बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सरकारी दावों की हकीकत यह है कि बंद कमरों में एक अधिनायकवादी सरकार का ड्राफ्ट पहले से तैयार है, जिसे छत्तीसगढ़ की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता पर जबरन थोपने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को गुमराह करने के लिए भाजपा सरकार यूसीसी के नाम पर जो सुझाव और सर्वे का नाटक रच रही है, वह पूरी तरह से फर्जी और पूर्व-नियोजित है। असली ड्राफ्ट दिल्ली के बंद कमरों में पहले ही लिखा जा चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की राय के लिए कोई स्थान नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक स्वायत्तता, मान्य प्रथा, परंपरा और रूढ़िगत अधिकारों पर एक सुनियोजित डाका है, जिसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की लगभग आधी आबादी पिछड़ों की है और लगभग 32 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अनुप्रासित जाति के लोग हैं जिनकी अपनी पारंपरिक, सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ हैं।

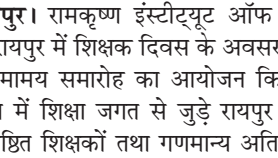
अनुमति के विपरीत निर्माण पर निगम चलाया बुलडोजर



रायपुर। चंगोराभाटा रिंग रोड नंबर-1 में कालकांत चंद्राकर ने नगर निगम की स्वीकृत अनुमति के विपरीत बन रहे व्यावसायिक भवन को जून-5 कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में मंगलवार को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। इससे पहले चंद्राकर को पहले नगर निगम अधिनियम के तहत नोटिस दिया फिर नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता लाल मेहनेद्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर मौजूद रहे।

नगर निगम ने साफ किया है कि शहर में भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और स्वीकृत अनुमति का पालन करना जरूरी है। अनुमति के विपरीत निर्माण मिलने पर संबंधित भवन मालिक या निर्माणकर्ता को नोटिस देकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल साइंस में शिक्षक दिवस मनाया गया



रायपुर। रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर भव्य एवं गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े रायपुर के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित शिक्षकों तथा गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अतिथियों का संस्थान की ओर से आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर. एस. गुप्तादीवान सर रहे। उनके साथ डॉ. ए. के. शुक्ला,प्रमोद दुबे, ज्ञानेश शर्मा, मूल्यांजय दुबे,नरेंद्र तिवारी,मणिधर दिवान, महेंद्र चौबे एवं स्मारिका नितिन राजपूत सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर डॉ. अरुणा चौबे, डॉ. मुक्ति मिश्रा, डॉ. किरण गुजपाल, डॉ. प्रकाश सलूजा, अशोक खरे, अर्चना खरे, गोपाल शुक्ला, सविता मिश्रा एवं प्रेमलता यादव का भी सम्मान एवं अभिनंदन किया गया।कार्यक्रम में अजय नाथडू,अमित चौबे, सौम्य चौबे, एवं ज्योति शर्मा की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के महत्व, अनुशासन, मेहनत, सकारात्मक सोच एवं जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन में केवल ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व निर्माण एवं उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने वाले मार्गदर्शक होते हैं।

नुआखाई सामाजिक एकता और भाईचारे का पर्व : पुरन्दर



रायपुर। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित नुआखाई भव्य शोभायात्रा के समापन समारोह में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरन्दर मिश्रा सम्मिलित हुए। इस अवसर पर रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी जी सहित समाज के गणमान्यजनों एवं बड़ी संख्या में समाजजनों की गरिमामयी उपस्थिति रही।समारोह को संबोधित करते हुए विधायक पुरन्दर मिश्रा ने कहा कि नुआखाई केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता, एकता और भाईचारे की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह पर्व हमें अपनी परंपराओं से जुड़ने के साथ-साथ आपसी प्रेम, सौहार्द और सहयोग की भावना को और मजबूत करने की प्रेरणा देता है। ऐसे सांस्कृतिक आयोजन समाज को एक सूत्र में बांधने तथा नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली परंपराओं और संस्कारों से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायक श्री मिश्रा ने नुआखाई पर्व की सभी प्रदेशवासियों एवं समाजजनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मंगलकामना की कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली लेकर आए।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही बंदियों की गणेश प्रतिमाएं



रायपुर। गणेशोत्सव के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रायपुर के बंदियों ने आस्था, रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण का अनुद्घा संगम प्रस्तुत किया है। आगामी गणेशोत्सव के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों द्वारा प्राकृतिक मिट्टी से लगभग 1 से 2 फीट आकार की 500 पर्यावरण-अनुकूल गणेश प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। इन प्रतिमाओं की खासियत यह है कि इनके निर्माण में प्राकृतिक मिट्टी एवं रंगों का उपयोग किया गया है तथा प्रतिमाओं में तुलसी सहित विभिन्न पौधों के बीज भी डाले गए हैं। गणेशोत्सव के पश्चात इन प्रतिमाओं का विसर्जन किए जाने पर इनमें मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप लेंगे। इस प्रकार ये प्रतिमाएं धार्मिक आस्था के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित संदेश को भी जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगी। केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों द्वारा विभिन्न कौशल विकास एवं उत्पादन गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में लगभग 10 बंदियों ने अत्यंत लगन, मेहनत और रचनात्मकता के साथ भगवान श्री गणेश की इन आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण किया है। यह पहल बंदियों के कौशल विकास, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें समाजोपयोगी एवं पर्यावरण हितैषी गतिविधियों से जोड़ने का सार्थक प्रयास है।

प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक माह भर चलेगा सेवा संकल्प अभियान छत्तीसगढ़ में जलेंगे 36 लाख आशीर्वाद के दीये

रायपुर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री/गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, स्वस्थ एवं ऊर्जावान जीवन के लिए 17 सितंबर को पूरे प्रदेश में 36 लाख आशीर्वाद के दीये प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र (बूथ) पर कम-से-कम 100 दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शर्मा मंगलवार को यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह अभियान मात्र एक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र



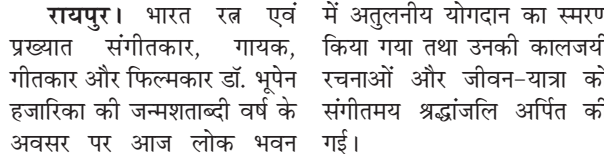
निर्माण का व्यापक जनांदोलन बनेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद (मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री) पर रहते हुए 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे वाले सेवा संकल्प अभियान और सेवा पखवाड़ा के विस्तृत कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि अभियान में हर गाँव, शहर, बूथ और परिवार की सक्रिय

चौकों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री देश के सभी जिला केंद्रों को एक साथ सम्बोधित करेंगे। इसी दरम्यान युवाओं की एक विशेष यात्रा प्रधानमंत्री के जन्मस्थान वडनगर से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक निकाली जाएगी। यह यात्रा विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों और कोरिया समेत कई क्षेत्रों में पहुँचेगी। अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी कार्यक्रम होगा। गुजरात की पवित्र नदियों के जल के साथ 250 बाइकों पर 500 यात्री वडनगर में हाटकेश्वर महादेव का अभिषेक

करेंगे और शर्मिष्ठा तालाब का जल लेकर 10 टोलियों में काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक एक माह तक चलने वाले सेवा मेरा योगदान अभियान में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक प्रशासनिक एवं सामाजिक स्तर पर सेवा गतिविधियों में भाग लेंगे। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने सेवा के रंग रंगीली प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख संस्थानों और घरों में 25 वर्षों के विकास कार्यों और सेवा भाव पर आधारित रंगीली प्रतियोगिताएँ एवं प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएंगी।

भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी पर लोक भवन में सांस्कृतिक संध्या



रायपुर। भारत रत्न एवं प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार और फिल्मकार डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर आज लोक भवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ. हजारिका के कला, संगीत एवं सांस्कृतिक क्षेत्र

में अतुलनीय योगदान का स्मरण किया गया तथा उनकी कालजयी रचनाओं और जीवन-यात्रा को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि डॉ. भूपेन हजारिका का संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि उसमें समाज, संस्कृति, प्रकृति, मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय एकता की गहरी अभिव्यक्ति थी। उन्होंने अपने गीतों और

संगीत के माध्यम से भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का कार्य किया। उनकी रचनाएँ आज भी लोगों को सामाजिक समरसता, भाईचारे और मानवीय मूल्यों का संदेश देती हैं।

सांस्कृतिक संध्या में हार्दिक कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के कलाकारों ने डॉ. भूपेन हजारिका के जीवन एवं रचनाओं पर आधारित नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की। नृत्य के माध्यम से उनकी रचनाओं और जीवन-यात्रा को प्रभावशाली ढंग से जीवंत किया गया। महाकालीबाड़ी एवं विश्वनाथ मंदिर समिति, पंडरी, रायपुर के कलाकारों ने डॉ. हजारिका द्वारा गाए प्रसिद्ध गीतों की भावपूर्ण संगीतमय प्रस्तुति दी।